

‘सभी जर्जर सरकारी भवनों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत करायें’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने पिपलोदी हादसे के बाद बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के भवनों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये

जयपुर, 25 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर झालावाड़ जिले के पिपलोदी ग्राम के सरकारी स्कूल में हुए दुखद हादसे के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने समस्त जिलों के जिला प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कार्यकारी एंजेंसी, समसा एवं आरएसआरडीसी सहित, संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी भवनों, विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों सहित अन्य सार्वजनिक भवनों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कार्य करवाए जाएं। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए, जो 5 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

शर्मा ने आगे कहा कि प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीपलोदी हादसे से हम सब दुखी हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ठोस और त्वरित कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए भवनों के निरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झालावाड़ के पीपलोदी में सरकारी विद्यालय की छत गिरने से हुआ हादसा दुखद एवं हृदय विदारक है। इस दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चों की मृत्यु से मन व्यथित है। राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्जर और उपयोग के लिए असुरक्षित पाए जाने पर भवनों को तुरंत खाली करवाया जाए और प्रभावितों का अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास किया जाए। उन्होंने कहा कि जर्जर स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित कर उनके लिए अस्थायी कक्षाओं का संचालन सामुदायिक भवनों या अन्य सुरक्षित स्थानों पर किया जाए।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2024-25 में प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थाओं और 750 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट घोषणाएं की थी। साथ ही, बजट 2025-26 में भी भवनविहीन व जर्जर विद्यालयों के नवीन भवनों के निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए 375 करोड़ रुपये का

■ **मुख्यमंत्री ने कहा कि असुरक्षित पाये जाने वाले भवनों को तुरंत खाली करवा कर प्रभावितों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास किया जाना चाहिये। गत दो बजट में राज्य सरकार ने विद्यालयों के भवन निर्माण व मरम्मत कार्यों के लिए 625 करोड़ रूपयों का आवंटन किया है।**

प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों की मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक के दौरान, पीपलोदी हादसे पर दो मिनट का मौन रखकर मृतक बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।

इस दौरान मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित, विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे तथा वीसी के माध्यम से संभागीय आयुक्तगण, जिला कलक्टरसं एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी जुड़े।

उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू

नयी दिल्ली, 25 जुलाई। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है और उनकी सहायता के लिए राज्यसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार को

■ **राज्यसभा महासचिव बनाये गये निर्वाचन अधिकारी**

सहायक निर्वाचन अधिकारी बनाया है। आयोग ने इस संबंध में गजट अधिसूचना शुक्रवार को जारी की। आयोग ने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस चुनाव के संबंध में निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है।

मानवाधिकार ... (प्रथम पृष्ठ का शेष) से बच्चे दुर्घटना के शिकार हो गए। ऐसे में यह जरूरी है कि घटना के दोषियों को सजा मिले और पीड़ित पक्ष को उचित क्षतिपूर्ति दी जाए।

गाज़ियाबाद की जूलरी शॉप में करोड़ों की लूट

गाजियाबाद, 25 जुलाई। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय वेश में आए हथियारबंद बदमाशों ने गुरुवार को दिनदहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम में घुसकर नग्न चार्ज्ड पर लाखों के गहने और नगदी लूट ली। लूटपाट की यह घटना ज्वेलरी शोरूम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

बुज बिहार में कृष्ण कुमार वर्मा की मानसी ज्वेलर्स नाम से ज्वेलरी की दुकान है। गुरुवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे दो बदमाश बाइक से दुकान पर

विपक्ष ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरेगे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और कई अन्य दलों के सांसद शामिल हुए। विपक्षी सांसद बैनर लेकर चल रहे थे जिसमें ‘एसआईआर- लोकतंत्र पर वार’ लिखा हुआ था। उन्होंने ‘एसआईआर वापस लो’ और ‘तानाशाही नहीं चलेगी’ के नारे लगाये।

एसआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ट्रेनी एसआई सहित, अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरी ओर, राज्य सरकार का कहना है कि पिपर लीक को लेकर व्यापक स्तर पर जांच चल रही है और अभी भी रह नहीं की जा सकती।

सरकार ने 25 ओटीटी चैनल बैन किए

नई दिल्ली, 25 जुलाई। भारत सरकार ने डिजिटल कंटेंट में बंद रही अश्लीलता को लेकर अब एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कथित तौर पर अश्लीलसामग्री दिखाने के लिए 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म और उनके संबंधित मोबाइल एप्लिकेशन पर बैन लगा दिया है। इनमें उल्लू, एल्ट, देसीफिलक्स और बिग शॉट्स जैसे लोकप्रिय नाम शामिल हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अलग-अलग जांच एजेंसियों से पूरी जानकारी हासिल करने के बाद यह फैसला लिया है।

■ **इनमें ऑल्ट, उल्लू, बिग शॉट्स, ड्रीम फिल्म्स आदि बड़े नाम शामिल हैं। आरोप है कि इन पर अश्लील सामग्री प्रसारित की जा रही थी।**

मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इस कदम का उद्देश्य अश्लील और भारतीय कानूनी एवं सांस्कृतिक मानकों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट के दिखाए जाने पर रोक लगाना है।

प्रतिबंधित एप्लिकेशन की लिस्ट में प्राइम प्ले, हंटर्स, ड्रीम फिल्म्स, रंगीन और नियोनएक्स वीआईपी भी शामिल हैं। इन प्लेटफॉर्म की अक्सर अपने अश्लील कंटेंट और एडल्ट सीरीज को लेकर आलोचना की जाती रही है, जिसके चलते ये प्लेटफॉर्म अक्सर निशाने पर भी रहते हैं।

सिंहस्थ कुम्भ के लिए नासिक के समीपवर्ती 5 रेल्वे स्टेशन विकसित होंगे

सिंहस्थ कुम्भ में तीन करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है

नयी दिल्ली, 25 जुलाई। महाराष्ट्र के नासिक-त्र्यंबकेश्वर में 2027 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ के मद्देनजर, रेलवे 1.011 करोड़ रुपये की लागत से आसपास के पांच रेलवे स्टेशनों को विकसित करेगा।

जिन स्टेशनों को विकसित किया जाना है, उनमें नासिक रोड, देवलाली, ओग 1, खेरवाड़ी और कसबे सुकेणे शामिल हैं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिंदू ने शुक्रवार को सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, प्रमुख मंडल के मंडल रेल अधिकारी (डीआरएम) और अन्य अधिकारियों ने मंत्रियों तथा रेलवे बोर्ड को इसकी योजना और कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी दी।

वैष्णव ने अधिकारियों से महाकुंभ 2025 के अनुभव से प्राप्त सर्वोत्तम

करौली में मारुति वैन-पिकअप भिड़ंत में चार महिलाओं की मौत

दुर्घटना में चार मृतक व 14 घायल जाटव परिवार के तथा एक ही कुटुंब के थे

करौली, 25 जुलाई (निं.सं.)। ईको वैन और एक पिकअप की आमने-सामने की टक्कर में चार महिलाओं की दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस हादसे में 11 महिलाएं, तीन पुरुष और तीन बालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति को उपचार के लिए जयपुर अस्पताल के लिए रैफर किया।

हिण्डीन क्षेत्र के बेड़ा वनकी गांव और मुड़ियांकापुरा निवासी एक वैन में करीब 17 महिला पुरुष और बच्चे करौली के पास माची गांव में एक रिश्तेदार महिला की मृत्यु के बाद तीए की बैठक में आए थे। वापस लौटते समय, करौली हिण्डीन सड़क मार्ग पर गुडला गांव के पास सड़क पर सामने से आ रही पिकअप गाड़ी से वैन की जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों की टक्कर को देख घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर

■ **हिण्डीन के बेड़ा वनकी गाँव व मुड़ियांकापुरा के 17 लोग, महिला, पुरुष व बच्चे, एक वैन में करौली के पास माची गाँव में तीये की बैठक में शामिल होने गये थे। लौटते समय गुडला गाँव के पास पिकअप से सीधी भिड़ंत हो गई।**

पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां से लोगों की मदद एवं निजी वाहनों से घायलों को करौली सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जिनमें से चार महिलाएं गुड्डी पत्नी विनोद 35, कमला पत्नी रेवती 40, शकुंतला पत्नी कजोड़ी जाटव 60 व मछला पत्नी जगदीश 40 को इयूटी डॉ. ने मृत घोषित कर दिया। इनके अलावा, वाहन चालक दत्त सिंह 50 गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उपचार के लिए जयपुर रैफर कर दिया । बाद में शवों का

सोमवार से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) रणनीति बदल दी है, वह अभी तक बिहार के मजदूत सूची पुनरीक्षण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और अब, प्रधानमंत्री मोदी के शनिवार को विदेश यात्रा से लौटने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर पर ध्यान देने की योजना बना रहा है। इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन संसद के भीतर और परिसर में, दोनों जगह जारी हैं।

कोचिंग सेंटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिए 15 निर्देश

नयी दिल्ली, 25 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने आत्महत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दो महीने के भीतर निजी कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण कराने सहित, 15 बाध्यकारी निर्देश जारी किए।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नీट) के अर्धवर्षी 17 वर्षीय एक छात्र की मृत्यु के मामले में सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए।

विशाखापत्तनम में छात्र की अपने छात्रावास की छत से गिरने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। यह दुखद घटना जुलाई में विशाखापत्तनम स्थित आकाश-बायजू संस्थान में हुई थी।

पीठ ने मृतक के पिता सुकदेब साहा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए, स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ये दिशानिर्देश जारी किए। अदालत ने इसके अलावा केन्द्र सरकार को 90 दिनों के भीतर एक हलफनामा दाखिल कर अनुपालन के संबंध में जानकारी देने का भी निर्देश दिया।

“उदयपुर फाइल्स” को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में जाकर बहस करें। हमने पहले ही 12 दिन खो दिए हैं। प्राधिकरण ने भी आदेश पारित कर दिया है।”

इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “12 दिन कोई नुकसान नहीं, जितनी पब्लिसिटी, उतना फिल्म को फायदा।”

हालाँकि भाटिया ने मदनी का हवाला देते हुए कहा, ऐसे लोग हमेशा ‘सुपर सेंसर’ की तरह काम करते हैं और फिल्म रिलीज पर रोक लगाने की

सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लेकर भागने लगे तो ग्रामीणों ने रोककर गाड़ियों के कांच तोड़ दिए। कुछ पुलिसकर्मियों के साथ मारपीत करने की बात भी सामने आ रही है।

बाद में, पुलिस ने लाटियां फटकारी और लोगों को खदेड़ा। लोग पहाड़ियों पर जा चढ़े। मौके पर पुलिस का बड़ी तादाद में जात्ता तैनात है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आने की भी सूचना थी, जिसके कारण प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र हो गए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी रात बस्तरकर दूसरे रास्ते से मनोहर थाना पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय के स्टाफ द्वारा लगातार ग्रामीणों की शिकायत को दरकिनार किया जा रहा था और ग्रामीणों के मना करने के बाद भी इमारत में बच्चों को बिठाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उन लोगों ने जब विरोध जताया तो स्कूल के स्टाफ ने उन्हें पुलिस कार्रवाई की

कोशिश करते हैं।

“1200 स्क्रीन बुक थीं, पैसा निवेश हो चुका है। हम किस बात को बढ़ावा दे रहे हैं? कि किसी की भावनाएं आहत हों और सिधे कोर्ट से स्टे ले आएं?”

अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया, बल्कि हाईकोर्ट को विवेकानुसार निर्णय लेने की छूट दी।

कोर्ट ने आदेश में कहा: “यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है। हाईकोर्ट स्वतंत्र है, जो भी आदेश उचित समझे, पारित कर सकता है।”

धमकी भी दी। जानकारी के अनुसार, मामले में एक्शन लेते हुए राउसथान सरकार के निर्देशों पर शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय के स्टाफ को निलंबित कर दिया गया है।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, मोना गर्ग, जावेद अहमद, रामविलास लववंशी, कन्हैयालाल सुमन और बद्रीलाल लोधा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने स्कूल के स्टाफ पर कार्यवाही करके इतिश्री कर ली है, जबकि बड़े अधिकारियों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीणों द्वारा विधायक गोविंद रानीपुरिया, जिला प्रशासन के आला अधिकारी एवं सभी स्थानीय अधिकारियों को बार-बार स्कूल की हालत से अवगत करवाया गया था, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, सब आश्वासन ही देते रहे और यह

धनखड़ को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

धनखड़ को उनके इस्तीफे के कुछ दिनों के बाद यह निमंत्रण दिया है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि पूर्व उपराष्ट्रपति विपक्ष न्योते पर डिनर में जाएंगे, इसकी संभावना न के बराबर है। (विपक्षी दलों की ओर से राज्यसभा के वर्किंग एडवाइजरी कमेटी की बैठक इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया गया। विपक्ष ने कहा कि 74 वर्षीय धनखड़ को राज्यसभा में अपना विदाई भाषण तक देने का मौका नहीं मिला। इसी मुद्दे को और जोर देने के लिए विपक्षी दलों ने एक विशेष फेयरवेल डिनर का आयोजन किया है।

धनखड़ को ...

हादसा हो गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मनोहर थाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) में हादसे में घायल बच्चों का हालचाल पूछा, भर्ती छात्रों की कुशलक्षेम पूछी और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने घायलों के परिजनों से बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधाया और सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और शोक संतप्त परिवारों के साथ अपनी पूरी सहानुभूति जताई। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। शिक्षा मंत्री ने राहतदात प्रशासन और चिकित्सकों को निर्देश दिए कि इलाज में कोई कमी न रह जाए और सभी आवश्यक संसाधन तुरंत उपलब्ध कराए जाएं।